(ख) इन दंगों के क्या कारण थे;

(ग) दंगा पीड़ित व्यक्तियों को क्या सहायता प्रदान की गई है;

(घ) दंगों को रोकने में असफलता के दोषी पाये गए अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(ङ) ऐसे दंगों को रोकने के लिए राज्य सरकारों को क्या निर्देश दिये गये हैं; और

(च) त्वरित कार्य बल के गठन की दिशा में अब तक कितनी प्रगति हुई है और इस संबंध में यदि कोई विलम्ब हुआ है, तो उसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. एम. जैकब) : (क) से (घ) लोक व्यवस्था को बनाए रखना संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II राज्य सूची में शामिल है और अतः यह राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों की जिम्मेदारी है। कर्नाटक राज्य सरकार से एक रिपोर्ट की मांग की गई है।

(ङ) केन्द्र सरकार ने साम्प्रदायिक सौहार्द की भावना बढ़ाने तथा साम्प्रदायिक हिंसा की रोक-थाम करने के लिए समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी किए हैं तथा उनको राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में परिचालित किया है।

(च) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की 10 बटालियनों को परिवर्तित करके रेपिड एक्शन फोर्स का गठन किया जा चुका है।

बंगलादेश से अवैध प्रवेश रोकने के लिए उपाय

267. **श्री राम जेठमलानी :**

सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सीमा सुरक्षा बल ने बंगलादेश से हमारे देश में लोगों के अवैध प्रवेश को रोकने के लिए सरकार को हाल ही में कतिपय उपायों का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो दिए गए सुझावों का ब्यौरा क्या है और उनके कार्यान्वयन पर कितना धन खर्च होने का अनुमान है;

(ग) क्या सरकार ने इन सुझावों को मान लिया है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और यदि हां, तो उनके कार्यान्वयन के संबंध में सरकार की क्या योजनाएं हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (घ) अवैध प्रवेश को रोकने के लिए विभिन्न उपाय करने पर समय-समय पर सभी संबंधित अभिकरणों के साथ परामर्श करके विचार किया जाता है। यह एक सतत् प्रक्रिया है।

Kashmir Problem

268. SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that, besides a political settlement of the Kashmir issue with militants, a number of administrative and other steps including delimitation of constituencies, both Parliamentary and Assembly, are required to be taken before general elections can be held in Jammu and Kashmir for restoration of a democratic Government in the State; and

(b) if so, the details thereof and the action taken so far in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI M. M. JACOB): (a) and (b) The number of Assembly seats have been increased by 11 by an amendment to the J&K Constitution in 1988 and the elections can take place only after the Delimitation work is completed by the Delimitation Commission, reconstituted in 1991.